

गरीबी के लिये जिम्मेदार कौन ॥

धनिखाहों की आमदनी में दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी और गरीबों की उसी गति से बढ़ती दीनता को देखकर सवाल उठने लगा है कि आखिरकार गरीबों के पतन के लिये जिम्मेदार कौन है सरकार समाजिक असमानता, खेत अथवा उद्योग धंधों के मालिक। गरीब के घर पैदा होने वाले बच्चे को दो जुन की रुखी सूखी रोटी मय्यसर नहीं होती। गरीब का बच्चा जैसे ही चलने फिरने की स्थिति में आता है तो वह भी मां बाप के साथ रोटी के लिये संघर्षरत हो जाता है। दूसरी तरफ अमीर का बच्चा ऐश आराम में पलता है। पढ़ लिखकर गद्दी सभाल लेता है। गरीब और गरीब का परिवार दिन भर की हाड़फोड़ मेहनत के बाद रोटी का इन्तजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता है वही दूसरी ओर अमीर का बेटा दौलत का पहाड़ जोड़ लेता है। सफेदपोश तो और भी तीव्रगति से रिकार्ड बनाने लगे हैं। ऐसी कौन सी मशीन इन पहाड़ खड़ा करने वालों के हाथ लग जाता है कि वे दौलत के पहाड़ पर खड़ा होकर मुस्कराते हैं। गरीब आमजन रोटी के लिये हाड़फाड़ मेहनत के बाद तंगहाल बसर करने को मजबूर है। आज हमारे सामने चिन्तन एवं शोध का विषय हो गया है गरीब और भूख।

आज के इस युग में समाज सेवा का भाव लुप्त हो रहा है। समाज सेवा का भाव वास्तव में महात्मा गांधी और डॉ अम्बेडकर में था। वे ही समाज सेवा के लिये जीये। बाबा साहेब ने तो सामाजिक अश्पश्यता का जहर पीकर भी गरीबों दीन वंचितों के लिये ही जीये। उनका जीवन ही दीन वंचितों को समर्पित रहा। दुर्भाग्यबस देश और जनता की सेवा की कसम खाने वाले ही भ्रष्टाचार, घोटाला, कबूरबाजी जैसे धिनौने कार्य में लिप्त पाये जा रहे हैं, क्षेत्रवाद फैला रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी रोजी की तलाश पर रोक लगाने को उत्सुक है जबकि देश के निवासी को देश के किसी भूभाग पर बसने और रोटी रोजी कमाने का अधिकार होना चाहिये दूसरी ओर व्यापारी मिलावट, नफाखोरी में लगा हुआ है उद्योगपति भी पीछे नहीं नजर आते। दरिद्र की बढ़ती दरिद्रता और अमीर का खड़ा होता धन दौलत का खड़ा पहाड़ देखकर सवाल उठता है सही मायने में गरीबी के लिये जिम्मेदार कौन हैं और देश के गरीबों का उद्धार कैसे हो। क्या लोकतन्त्र के पहरेदार ऐसे ही सफेद को काला करते रहेंगे। उद्योगपति, व्यापारी धन दौलत पहाड़ खड़ा करते रहेंगे। सफेदपोश विदेशी बैंकों में धन भरते रहेंगे। क्या गरीबी को सरकार काबू में कर पायेगी। क्या गरीबों का उद्धार प्रजातन्त्र के युग में हो पायेगा। क्या लालफीताशही गरीबों का साधन सम्पन्न बनाने में समर्थ होगी। क्या बेरोजगारी भत्ता और वजीफा भर से देश का युवा जीवन यापन कर पायेगा। सही मायने में गरीबी उन्मूलन में सामाजिक असमानता और आर्थिक/उद्योग/व्यापार/धंधे का केन्द्रीकरण गरीबी को हवा देने में सहायक साबित हो रहा है। इस हवा का रुख सरकार बदल सकती है पर सरकार चलाने वाले अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी के साथ देश और समाज के हित में करें।

इन प्रश्नों पर गौर किया जाये तो उत्तर नकारात्मक मिलता है। सच तो ये है कि गरीबी के लिये जिम्मेदार नीति, नीति निर्धारक और सामाजिक कुव्यवस्था का मजबूत हाथ भी हैं। गरीबी के चक्रव्यूह को सरकार तो तोड़ सकती है पर इस सरकार में शामिल लोग सबसे पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। जनता का ख्याल तो उन्हे सिर्फ चुनाव के वक्त आता है। सुक्ष्म चिन्तन किया जाये तो गरीबी के लिये हमारी सरकार काफी हद तक जिम्मेदार है क्योंकि वह भ्रष्टाचार, घोटाला, नफाखोरी मिलावट महंगाई को रोक नहीं पा रही है और ये आर्थिक अपराध गरीबी से उबरने नहीं दे रहे हैं। गरीब ही नहीं देश भी गरीबी कर्ज के दलदल में फसता जा रहा है। सरकार को इस तरह के अपराधों पर शिकंजा कसना चाहिये। हर हाथ को रोजगार मिले ऐसे प्रावधान होने चाहिये। मालिकों उद्योगपतियों को भी चाहिये कि वे गरीब मजदूरों की मदद करें। इस मदद से गरीब मजदूर का ही भला नहीं होगा, उद्योगपति और देश को भी लाभ होगा। मालिक लोग मजदूरों को चिकित्सा सुविधा दें, बीमा सुविधा दें। जो मजदूर अशिक्षित और खेत मालिकों के खेतों में काम कर रहे हैं उन्हे भी मूलभूत सुविधाये मिले और मालिक मजदूर के बीच खड़ी दीवार को तोड़े। मजदूरों से सीधे संवाद स्थापित करें। इससे मानवीय रिश्ते को मजबूती मिलेगी और यह मजबूती

उद्योग और उद्योगपति के लिये फायदेमंद साबित होगी और मजदूर अपने को अलग नहीं समझेगा । वह लाभ / हानि के मुद्दों पर भी चिन्तन करेगा ।

सरकार भूमिहीन खेतिहार मजदूरों को खेती करने की जमीन उपलब्ध कराये । पढ़े लिखे बेरोजगारों को छोटे बड़े उद्योग धंधों की स्थापना करने एवं उनके संचालन के लायक शिक्षा दी जाये । कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतारी की जाये ताकि वे पढ़ लिख कर रोजगार धंधा में लग सके और देश की तरक्की में सहभागी बने । छात्रवृत्ति खासकर गरीब तबके शिक्षार्थियों के लिये वरदान साबित होती है । रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाये । ग्रामीण स्तर तक प्रोफेशनल्स इंजुकेशन की पहुंच हो जिससे गांव के होनहार शिक्षा प्राप्त कर विकास की धारा से जुड़ सके । यदि युवा शक्ति नव निर्माण एवं रोटी / रोजी से जुड़ गयी तो गरीबी का उन्मूलन सुनिश्चित है ।

समाज भूमण्डलीयकरण के युग में सामाजिक परिवर्तन में आगे आये । सामाजिक सोच में बदलाव भी गरीबी उन्मूलन में काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है । वर्तमान युग में भी सामाजिक परिवर्तन की अत्यन्त आवश्यकता है । धार्मिक जातीय फंसाद भी गरीबी के लिये जिम्मेदार हैं । इसलिये सामाजिक समानता स्थापित हो । चीन जैसे देश के लिये जनसंख्या अभिशाप नहीं है तो हमारे देश के लिये क्यों न देश में हर क्षेत्र में सम्भावनाये विद्यमान है चाहे वे कृषि का क्षेत्र हो या उद्योग का या अन्य कोई क्षेत्र । देश के धनाद्यों चाहे तो गरीबी का उन्मूलन हो सकता है । इस सम्भावना पर सरकार को बारीकी से विचार करना होगा । यदि देश से गरीबी मिट गयी और सामाजिक समानता का साम्राज्य स्थापित हो गया तो आतंकवाद जैसी महामारी का खतरा भी टल सकता है । रोजगार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की दशा में बन्दूक थामने वाले हाथ असामाजिक तत्वों से हाथ मिलाने वाले हाथ रोजगार अपनायेगे । बन्दूक नहीं थामेगे । असामाजिक तत्वों के कुचक के शिकार नहीं होगे । सामाजिक बुराईया बार बार सिर नहीं उठायेगी । सरकार को ठोस कदम उठाने होगे । सामाजिक एवं आर्थिक पहलूओं पर विचार मंथन के साथ राजनैतिज्ञ दृढ़ इच्छा शक्ति का भी परिचय देना होगा । यदि सरकार सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिज्ञ कारकों में समन्वय स्थापित कर गरीबी उन्मूलन का महासमर नहीं जीत पायी तो इस आरोप से नहीं बच पायेगी कि सही मायने में सरकार ही गरीबी के लिये है ।